भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3912

बुधवार, दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

ओडिशा में पीएम-एसजीएमबीवाई

3912. श्री प्रदीप पुरोहित: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओडिशा में विशेष रूप से बरगढ़ और झारसुगुड़ा सहित आज की तिथि तक प्रधान मंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान ओडिशा में इस योजना के अंतर्गत जारी की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता (राजसहायता) का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर के लाभ सरकारी आवासीय परिसरों, कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, पंचायत भवनों, अस्पतालों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों को देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान बरगढ़ और झारसुगुड़ा सहित ओडिशा में लाभार्थी परिवारों द्वारा कुल कितनी बिजली उत्पन्न की गई तथा बिजली की खपत एवं बिजली के बिलों में कितनी बचत का अनुमान है; और

(ङ.) ओडिशा में विशेष रूप से बरगढ़ और झारसुगुड़ा सहित ग्रामीण तथा आकांक्षी जिलों में योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा अगले दो वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना (PMSG: MBY) के तहत, फरवरी 2024 में इसकी शुरुआत के बाद से, दिनांक 07.08.2026 की स्थिति के अनुसार, ओडिशा राज्य में कुल 3,08,894 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 1,63,811 रूफटॉप सोलर (RTS) सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे 1,64,903 परिवार लाभान्वित हुए हैं साथ ही, केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) के रूप में 746.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। बारगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों सहित जिला-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) PMSG: MBY का एक प्रमुख घटक रूफटॉप सोलर स्थापित कर सरकारी भवनों की परिपूर्णता है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें विभिन्न कार्यान्वयन मॉडल दिए गए हैं। साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को लगाने का अनुभव रखने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) को केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) की इमारतों पर रूफटॉप सोलर लगाने में सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है।

तथापि, सरकारी इमारतों के लिए कोई केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) उपलब्ध नहीं है, क्योंकि रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना उनके लिए CFA के बिना भी आर्थिक रूप से व्यवहार्य है।

(घ) एक सामान्य धूप वाले दिन में, देश में एक मानक 1 kWp रूफटॉप सोलर प्लांट से 3 से 4 kWh बिजली उत्पन्न होने का अनुमान है।योजना के तहत RTS सिस्टम लगवाने वाले ओडिशा राज्य के उपभोक्ताओं (बरगढ़ और झारसुगुड़ा ज़िलों सहित) के बिजली बिलों में भारी कमी आई है। ओडिशा की DISCOMs के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत RTS सिस्टम लगने के बाद से 37,678 से अधिक लाभार्थियों का बिजली की खपत के आधार पर किसी न किसी महीने या बिलिंग अवधि में बिजली बिल शून्य आया है जो उनकी स्वयं की बिजली खपत पर निर्भर करता है।

(ङ) पीएमएसजी एमबीवाई एक मांग-संचालित योजना है और इस योजना के अंतर्गत किए गए लक्ष्यों का कोई राज्य-वार आवंटन नहीं है।

ओडिशा में विशेष रूप से बारगढ़ और झारसुगुड़ा सहित ग्रामीण और आकांक्षी जिलों में इस योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने निम्नलिखित सहित कई कदम उठाए हैं:

- पर्याप्त और योग्य विक्रेताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विक्रेताओं के पंजीकरण की सरलीकृत प्रक्रिया।
- तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता को माफ करके और 10 किलोवाट तक ऑटो लोड वृद्धि शुरू करके नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- नेट मीटरिंग समझौते को नेशनल पोर्टल पर आवेदन का हिस्सा बना दिया गया है, जिससे अलग समझौते की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
- डिस्कॉम अधिकारियों सहित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- राज्यों, डिस्कॉम और बैंकों सहित विभिन्न स्तरों पर योजना की प्रगति की नियमित निगरानी। इसके अलावा, समय-समय पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों से रेपो रेट प्लस 50 बीपीएस (वर्तमान में 5.75% प्रति वर्ष) की रियायती ब्याज दर पर बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध है, जिसकी अवधि 10 वर्ष है। जनसमर्थ पोर्टल के एकीकरण के साथ नेशनल पोर्टल पर ही ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है।

- शिकायतों के समय पर समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। 15555 टेलीफ़ोन नंबर वाला एक कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है।
- देश भर में प्रमुख समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन, टीवी विज्ञापन अभियान, क्षेत्रीय चैनलों सहित एफएम स्टेशनों पर रेडियो अभियान आदि जैसे जागरूकता और प्रचार कार्यक्रमों के माध्यम से योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल के अंतर्गत 1.50 लाख RTS सिस्टम स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।

इसके अतिरिक्त, MNRE और REC लिमिटेड, PMSG: MBY के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (NPIA) के रूप में, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी DISCOMs के साथ निकट समन्वय में काम करते हैं।

अनुलग्नक

'ओडिशा में पीएम-एसजीएमबीवाई' के संबंध में दिनांक 12.08.2026 को पूछे गए लोक सभा आतारांकित प्रश्न सं. 3912 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

PM-SGMBY के तहत हुई प्रगति का जिलावार विवरण: ओडिशा राज्य में एमबीवाई (दिनांक 07.08.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	जिला	आवेदन (संख्या)	स्थापना (संख्या)	परिवार (संख्या)	जारी सब्सिडी राशि (करोड़ में)
1	अनुगुल	7424	3058	3058	15.70
2	बलांगीर	11665	6012	6020	26.86
3	बालेश्वर	26727	15343	15343	56.48
4	बरगढ़	12926	8081	8081	38.96
5	भद्रक	9751	5583	5587	20.32
6	बौध	2974	1075	1075	5.11
7	कटक	22498	12624	13329	64.49
8	देवगढ़	1640	811	811	3.85
9	ढेंकनाल	10576	4780	4784	24.62
10	गजपति	5073	1482	1482	4.29
11	गंजम	24112	13811	13811	55.21
12	जगतसिंहपुर	12562	5903	5903	26.28
13	जाजापुर	16024	7986	7986	34.32
14	झारसुगुड़ा	4716	2737	2737	14.94
15	कालाहांडी	8685	5154	5154	25.04
16	कंधमाल	7890	642	642	2.40
17	केंद्रपाड़ा	8118	4531	4535	15.00
18	केंदुझार	9524	5009	5025	20.79
19	खोरधा	22415	13704	13920	86.32
20	कोरापुट	3369	1148	1148	6.89
21	मलकानगिरी	2116	703	703	2.84
22	मयूरभंज	14212	8961	8961	36.99
23	नबरंगपुर	4154	1320	1320	4.20
24	नयागढ़	6792	2915	2915	14.21
25	नुआपाड़ा	10584	7689	7689	28.62
26	पुरी	11625	5695	5695	20.65
27	रायगढ़	3877	1412	1412	7.98
28	संबलपुर	10348	5712	5712	30.98
29	सोनपुर	5200	3049	3049	15.76
30	सुंदरगढ़	11317	6881	7016	36.56
	कुल	**3,08,894**	**1,63,811**	**1,64,903**	**746.67**

*****